



15वें वित्त आयोग की भारतीय रज़िर्व बैंक के साथ बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन श्री एन.के. सहि ने मुंबई में भारतीय रज़िर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों के साथ बैठक की जिसमें कुछ प्रमुख मामलों पर वस्तुतः चर्चा की गई। गौरतलब है कि वित्त आयोग बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अर्थशास्त्रियों के साथ भी बैठकें आयोजित करेगा।

प्रमुख बिंदु

- चर्चा में शामिल कुछ प्रमुख मुद्दे नमिनलखित हैं-
 - बैठक में 'संबंधित राज्य सरकारों के लिये राज्य वित्त आयोगों के गठन की आवश्यकता' के साथ ही 'सार्वजनिक क्षेत्र हेतु वित्तीय ऋण की आवश्यकता' पर भी चर्चा की गई।
 - वित्त आयोग की नरंतरता (Continuity of the Finance Commission) राज्यों के वित्तीय प्रबंधन के लिये आवश्यक है, विशेषकर वर्तमान स्थिति में जब मध्यावधि समीक्षा नहीं हुई है क्योंकि पहले यह समीक्षा योजना आयोग के द्वारा की जाती थी।
 - परवियय संहिता (Expenditure Codes) की आवश्यकता, क्योंकि परवियय कानून राज्य-दर-राज्य परिवर्तित होते हैं।
 - विकास और महंगाई दर में राज्यों की भूमिका, उदाहरण के लिये व्यापार सुगमता (Ease of doing Business) के संबंध में राज्यों की भूमिका।
- भारतीय रज़िर्व बैंक ने वित्त आयोग को वर्ष 2019-20 के लिये राज्य सरकार वित्त (State Government Finances) वषिय पर वस्तुतः जानकारी दी। इसके प्रमुख तथ्य नमिनलखित हैं-
 - सरकारी वित्त की संरचना में बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था में राज्यों की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हुई है।
 - 2019-20 के बजट अनुमानों (Budgeted Estimate) में राज्यों का वित्तीय घाटा नमिन स्तर पर रहने की बात कही गई थी परंतु संशोधित अनुमान (Revised Estimate) और वास्तविक स्थिति भिन्न है।
 - कुछ वशिष्ट कारकों से वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे कारकों में 'उदय' (UDAY) और कृषिकर्ज माफी तथा आय समर्थन योजना आदि शामिल हैं।
 - ब्याज अदायगी प्रक्रिया को उदार बनाए जाने के बावजूद जीडीपी की तुलना में ऋण प्रतशित बढ़ रहा है।

भारतीय रज़िर्व बैंक ने राज्य सरकारों द्वारा बाज़ार से ऋण प्राप्त करने की चुनौतियों के मामले में भी जानकारी दी। इसके प्रमुख तथ्य नमिनलखित हैं-

- सीएसएफ/जीआरएफ कोष को मज़बूत करना और कोष को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन।
- नकद प्रबंधन- राज्यों द्वारा नकद क्षमता को बेहतर बनाना और अल्प अवधि के ऋणों के लिये बेहतर अवसरों के निर्माण का अनुरोध।
- प्रकटीकरण- महत्त्वपूर्ण आँकड़ों, बजट तथा वित्तीय आँकड़ों को सामने रखना।

15वाँ वित्त आयोग (Finance Commission-FC)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की।
- 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-25 तक होगा। अभी तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है।
- 14वें वित्त आयोग की सफारिशें वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिये वैध हैं।
- ध्यातव्य है कि 27 नवंबर, 2017 को श्री एन.के. सहि को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नयोगी थे।
- श्री एन.के. सहि भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008-2014 तक बहिर से राज्य सभा के सदस्य भी रह चुके हैं।

वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों?

- भारत की संघीय प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति एवं कार्यों के वभाजन की अनुमति देती है और इसी आधार पर कराधान की शक्तियों को भी केंद्र और राज्यों के बीच वभाजित किया जाता है।

- राज्य वधायिका को अधिकार है कविह स्थानीय नकियों को अपनी कराधान शक्तियों में से कुछ अधिकार दे सकती है ।
- केंद्र कर राजस्व का अधिकांश हसिसा एकत्र करता है और कुछ नशिचति करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता है ।
- स्थानीय मुद्दों और ज़रूरतों को नकिटता से जानने के कारण राज्यों की यह ज़मिमेदारी है कविे अपने कषेत्रों में लोकहति को ध्यान में रखें । हालाँकि इन सभी कारणों की वज़ह से कभी-कभी राज्यों का खर्च उनको प्राप्त होने वाले राजस्व से कहीं अधिक हो जाता है ।
- इसके अलावा, वशाल कषेत्रीय असमानताओं के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं ।
- इन असंतुलनों को दूर करने के लयि वत्ति आयोग द्वारा राज्यों के साथ साझा कयि जाने वाले केंद्रीय नधियों की सीमा तय करने की सफिरशि की गई है ।

स्रोत- पीआइबी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/meeting-of-the-15th-finance-commission-with-the-rbi>

